Neglect of Historical Monuments

[†]श्री ओबैदुल्लाह खान आज़मी (मध्य प्रदेश): सदरे मोहतरम, मैं आपके जिरए इस हाऊस की तवज्जोह तारीखी इमारतों और यादगारों की देखरेख और हिफाजत में महकमा आसारे कदीमा, म्युनिसपल कारपोरेशन और दीगर मुतालिका महकमों की गफलत की तरफ दिलाना चाहता हूँ।

सदर साहब, यह हमारी तारीखी इमारतें और यादगारें हमारे मुल्क की ही नहीं बल्कि दुनिया की अज़ीम विरासतों में शामिल हैं, लेकिन आए दिन हमें इन यादगारों की ख़स्ता हाली के बारे में ख़बरें मिलती हैं । हद यह है कि जो तारीखी यादगारें महकमा आसारे कदीमा की तहफ़्कुज याफ्ता इमारतों की लिस्ट में हैं वे भी गफलत का शिकार हैं, जिसके नतीजे में वे लोगों के नाजायज़ कब्ज़े और माजायज़ तामीरात का निशाना बनी हुई हैं । कानून के मुताबिक तारीखी यादगारों के सौ मीटर के दायरे में कोई तामीर नहीं की जा सकती और दो सौ मीटर के दायरे में कोई तामीर नहीं की जा सकती और दो सौ मीटर के दायरे में कोई तामीर मुतालिक़ा महकमे की इजाज़त के बगैर नहीं की जा सकती, लेकिन होता यह है कि इन इमारतों के अहाते में ही लोग बेघड़क नाजायज़ तामीरात खड़ी कर रहे हैं या इन इमारतों को कूड़ेदान के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आसारे क़दीमा, दिल्ली म्युनिसपल कारपोरेशन, दिल्ली पुलिस और दूसरे मुतालिका महकमे के लोग हाथ पर हाथ रखे खामोश तमाशाई बने बैठे हैं । आम तौर पर इनकी बिल्डरों या नाजायज़ कब्जा और नाजायज़ तामीर करने वालों के साथ मिलीभगत होती है । दिल्ली में कोटला मुबारकपुर में मुबारकशाह का मक़बरा और मोहम्मदप्र गांव में तीन बुर्जी की यादगारें इसकी चंद मिसाले हैं ।

चुनांचे मैं मुतालबा करता हूँ कि पूरे मुल्क में और खासतौर से दिल्ली में जितनी भी तहफ्कुज याफ्ता इमारते हैं या जो हमारी विरासंत का हिस्सा हैं, उनमें से नाजायज़ कब्ज़ा हटाने और नाजायज़ तामीरात गिराने की कार्यवाही फौरन की जाए, उनकी देखरेख का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए और यहां सय्याहों के लिए सहुलियात पैदा की जाएं। शुक्रिया।

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Sir, I associate myself with it.

श्री बाल कवि बैरागी (मध्य प्रदेश) : सभापति जी, मैं इससे अपने को संबद्ध करता हूँ।

Allocation of Indus Water to Gujarat

SHRI LALITBHAI MEHTA (Gujarat): Sir, my Special Mention is regarding the allocation of Indus Water to Gujarat.

Sir, the Indus basin Map and National Commission for integrated water resources of Government of India Map of 1999 show Kachchha region of Gujarat in Indus Basin.

According to the international water agreement, waters of the eastern rivers of Indus basin are allocated to India as per "Indus Water Treaty".

[†] Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the debate.

The waters of Eastern rivers are estimated at 17.17 MAF.

The States of Haryana, Punjab, Rajasthan, Delhi and Jammu and Kashmir are the beneficiaries in receiving the Eastern river waters.

Gujarat is entitled to Indus Basin water as the region of Kachchha falls in the Indus Basin.

The allocation of Eastern river waters is reviewed from time to time based on availability of water and geographical situation of States.

The hydrological conditions and geographical situation of Kachchha are the same as that of Rajasthan which should be considered while reviewing the allocation of water under the "Indus Water Treaty".

The hon. Chief Minister of Gujarat in the fifth meeting of the National Water Resources Council held at New Delhi on 1st April, 2002 has requested the hon. Prime Minister for allocation of Indus Basin Water to Kachchha region of Gujarat but no response is received till today.

Gujarat faces acute water shortage and the region of Kachchha is vulnerable to scarcity, drought and famine.

Sir, I request that water of Sindhu should be allocated and Gujarat must be included in allocation of waters of Eastern rivers.

SHRI A.K. PATEL (Gujarat): Sir, I associate myself with it.

Destruction of Food and Horticulture Crops and Killing of People by Wild Elephants in Karnataka and other States

SHRI M.V. RAJASHEKHARAN (Karnataka): Sir. the conflict between man and animal has assumed serious proportions. Now, we find that the killings of wild elephants have caused enormous destruction of food This has been happening in Karnataka, and horticulture crops. Chhattisgarh, Bihar and Jharkhand. Sir, in Karnataka, this is creating serious problems to the farming community living in the outskirts of Bangalore city. Unless barriers are created, it is difficult to contain this menace. Therefore, the Central Government should provide sufficient funds to the State of Karnataka. The Central Government should not just say that it is the responsibility of the States. Tamil Nadu has also been very much affected by this problem of elephant menace. Sensitive areas must have barriers to stop the menace of wild elephants. It is a national problem. The Government of India gives only Rs. five crores, annually. This amount is not